दिनांक 8 जुलाई 2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 60186 घरों का अब तक हो चुका है सर्वे

भिलाईनगर/शहरी गरीबों को सर्वसुविधायुक्त सभी मौसम में टिकने वाले पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन 2022 पूरे देश में लागू किया गया है। प्रदेश में यह योजना तीन चरणों में लागू होना है। मिशन का मुख्य उद्देश्य निम्न विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकताओ को पूरा करना है:- शहर की स्थायी झुग्गी बस्ती की भूमि का संसाधन के रुप में उपयोग करते हुए निजी बिल्डर्स की भागीदारी से झुग्गी बस्ती का पुर्नविकास , आवास निर्माण हेतु बैंक ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर एवं मध्य आय वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन , अस्थायी गंदी बस्ती एवं अव्यवहार्य स्थायी झुग्गी बस्ती के हितग्राहियों के व्यवस्थापन हेतु नगरीय निकाय/हाउसिंग बोर्ड/विकास प्राधिकरण एवं बिल्डर्स/डेव्हलपर्स की भागीदारी से किफायती आवास का निर्माण करना , हितग्राही को 15-30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु सब्सिडी। राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा नगर पालिक निगम , भिलाई में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कुल संपादित डोर टू डोर सर्वे संबंधित- घटक बीएलसी कुल संपादित सर्वे 9782 प्रतिशत 16.25, एएचपी 41346 प्रतिशत 68.69, आईएसएसआर 7317 प्रतिशत 12.15, सीएलएसएस 1741 प्रतिशत 02.89 कुल 60186 प्रतिशत 100%। हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण (मोर जमीन मोर मकान) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का विवरण कुल स्वीकृत आवास- 5067, कुल पात्र हितग्राही-3497, कुल अटैचमेंट हितग्राही-2819, कुल पूर्ण आवासों की संख्या- 938, कुल निर्माणाधीन आवासों की संख्या- 668 है। साझेदारी में किफायती आवास घटक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का वितरण कुल स्वीकृत आवास- 5478, कुल अटैचमेंट हितग्राही-2738, कुल पूर्ण आवासों की संख्या- 308, कुल निर्माणाधीन आवासों की संख्या- 2743 है। ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी घटक के अंतर्गत कुल 1741 आवेदन आवेदन पोर्टल में दर्ज है जिसका विवरण 392 कुल स्वीकृत ऋण प्रकरण् , 5633.27 लाख रुपये ऋण स्वीकृत , 4105.08 लाख रुपये ऋण स्वीकृत, 702.16 लाख रुपये सब्सिडी की राशि हितग्राहियों के ऋण खाता में प्राप्त स्वीकृत।

जनसम्पर्क अधिकारी

जल है तो कल है जल ही जीवन है!